1	2	3
	देयताएं	
47.	अपर किथुन जलाशय सहित पूरी हो गयी परियोजनाओं की देयताएं	28.68
48.	आठवीं योजना की नयी स्कीमें	20.00
49.	अन्य क्षेत्र	8.00
50.	जनजातीय उपयोजना	2.00
	जल विकास	
51.	राष्ट्रीय जल प्रबन्ध सहित उन्नत जल प्रबन्ध	25.00
52.	बांध सुरक्षा सहित विद्यमान सिंचाई प्रणाली की मरम्मत	50.00
53.	विद्यमान सिंचाई प्रणाली की विशेष मरम्मत	8.00
54.	जल विकास सर्विस	40.00
55.	बाद में किया जाने वाला मूल्यांकन	5.00
	कुल	1927.17

टिप्पणी :—विद्यमान वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा उपर्युक्त किसी भी योजना को कोई विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान नहीं की गयी है ।

देश में जल संसाधनों से उत्पादित विद्युत

3488. **श्री गया सिंह** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उपलब्ध जल संसाधनों से अब तक कितने प्रतिशत विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) सभी उपलब्ध जल संसाधनों से कितनी ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) बिहार के लिये इस संबंध में क्या योजना तैयार की गई है और उसके तहत कितने प्रतिशत ऊर्जा का उत्पादन किया जाना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पी के थुंगन : (क) से (ग) देश की जल-विद्युत क्षमता का आकलन वृहद एवं मध्यम जल विद्युत स्कीमों से 60 प्रतिशत लोड फैक्टर पर 84044 मेगावाट किया गया है जिनमें से 14.5 प्र. का उत्पादन विद्यमान जल विद्युत स्कीमों से किया जा रहा है। स्वीकृत एवं निर्माणाधीन जल विद्युत स्कीमें अनुमानित क्षमता का 7.16 प्र. का और उपयोग करेंगी। जल विद्युत क्षमता के उपयोग में वृद्धि करने पर विचार करने के लिए, राष्ट्रीय विकास परिषद के आग्रह पर एक सचिव स्तरीय दल का गठन किया गया है।

(घ) बिहार की जल विद्युत क्षमता का अनुमान 60 प्रतिशत लोड फैक्टर पर 538 मेगावाट लगाया गया है, जिसमें बिहार में पड़ने वाले दामोदर घाटी निगम की क्षमता भी शामिल है। 300.6 मेगावाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता वाली 6 जल

विद्युत स्कीमें दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में 144 मेगावाट सहित उपर्युक्त क्षमता का 18.43 प्र. का उपयोग करती हैं। 5 जल विद्युत स्कीमें इस समय निर्माणाधीन हैं जो 60 प्र. लोड फेक्टर पर 231.78 मेगावाट क्षमता का उपयोग करेंगी। बिहार में प्रचालित और निर्माणाधीन स्कीमें ही 61.51 प्र. की कुल क्षमता का उपयोग करेंगी।

महानदी बेसिन में जल संसाधनों के लिये व्यापक योजना

3489. चौधरी हरि सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानदी बेसिन में जल संसाधनों के प्रबन्धन के लिए व्यापक योजना को अंतिम रूप देने के संबंध में प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

(ख) क्या उक्त व्यापक योजना के अन्तर्गत कुछ योजनाओं को कार्यान्वित करने का कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने महानदी बेसिन में बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिए तत्काल वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) वर्ष 1987 में अपनाई गई राष्ट्रीय जल नीति में नदी बेसिन को जल संसाधनों की आयोजना के मुख्य यूनिट के रूप में मानने की आवश्यकता को समझा गया तथा राज्यों में बहुविषयक यूनिटों की स्थापना द्वारा सिंचाई सहित विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल संसाधनों के एकीकृत एवं उनके इष्टतम विकास हेतु नदी बेसिन मास्टर योजनाएं तैयार करने पर बल दिया गया है। इसके आधार पर अप्रैल, 1990 में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा नदी बेसिन मास्टर योजनाएं तैयार करने हेतु राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को दिशानिर्देश जारी किए गये हैं। वर्तमान नीति के अनुसार, जल संसाधनों के विकास की परियोजनाओं की आयोजना, निर्माण, वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

(ग) ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

छोटी-बड़ी परियोजनाओं को पूरा किया जाना

3490. श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री राम जेठमलानी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1951 में हमारे देश में 264 लघु/बड़ी परियोजनाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया था और वर्ष 1992 तक उनमें से 102 परियोजनाओं को पूरा किया जा सका है;

(ख) क्या यह भी सच है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रति हेक्टेयर सिंचाई क्षमता पैदा करने के लिये 22,956 रुपए लागत आती थी जो सातवीं योजना के दौरान बढ़कर 42,700 रुपए हो गई;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और क्या यह भी सच है कि परियोजनाओं के निर्धारित समय पर पूरा न होने के कारण उनकी लागत में वृद्धि होती है और देश में प्रति हेक्टेयर सिंचाई क्षमता बढ़ती जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951—56) में क्रियान्वयन के लिए शुरू की गई 44 वृहद, 169 मध्यम और 12 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण सिंचाई परियोजनाओं में से, मार्च 1992 तक 40 वृहद, 168 मध्यम और 12 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाएं पूरी की गई। 4 वृहद परियोजनायें नामत: भाखड़ा, तुंगभद्रा बांध तथा दायां तटनहर, हरीशचन्द्र सागर और बसन्त तथा बाणसागर